

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

दिनांक: 26.02.2020

विषय - समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतिकरण।

जल संसाधन विकास और संबद्ध विषयों से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है। इन समाचारों की कटिंग की सॉफ्ट कॉपी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

संलग्नक: उपरोक्त

अंजना
26.02.2020

वरिष्ठ कलाकार

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

सहायक निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे० संजीव
26/02/2020

उप निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे० विवेक
26/02/2020

निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे० पुष्पिता झा
26-02-2020

सेवा में,

अध्यक्ष, के. ज. आ., नई दिल्ली

जानकारी हेतु - सभी संबंधित केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर देखें।



Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
 The Times of India (New Delhi)
 The Indian Express (New Delhi)
 The Hindu (Delhi)
 Pioneer (Delhi)
 राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☒ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Roorkee Water Conclave to focus on climate change impact

STATESMAN NEWS SERVICE
 NEW DELHI, 25 FEBRUARY

51-26

The hydrological aspects of climate change, or the impact of climate change on supply and management of water resources, will be the focus of a three-day conclave being jointly organised by the Indian Institute of Technology Roorkee (IIT Roorkee) and National Institute of Hydrology Roorkee (NIH Roorkee).

The Roorkee Water Conclave (RWC) at IIT Roorkee, from 26-28 February, would be the first edition of this bi-annual event, an official communique said. Upendra Prasad Singh, Secretary, Union Ministry of Jalshakti, Department of Water

Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, will inaugurate the conclave. International experts from the US, Canada, Spain, Germany, Japan, Netherlands, UK, Australia, Austria and Italy, as well as experts from top national institutes such as IISc, IITs, JNU, and ISRO will share their knowledge and experiences during the conclave.

In all, 23 foreign experts and 11 experts from India will deliver keynote talks.

The deliberations during the three-day conclave would cover several important topics including hydrologic extremes such as floods and droughts and their management, modeling and

assessment of water resources under changing climate, policy framework and climate change adaptation strategies, water-energy-food nexus and river dynamics.

The discussions during the conclave are expected to yield a better understanding of the impacts of climate change on the water sector, document the current state of science/technology, gaps and identify opportunities for further research and development.

Talking to the media, Sharad K Jain, Director, NIH Roorkee, opined, "Globally, climate change is conferred as the most critical challenge as it has an adverse

impact on mankind. Today, we are here to talk on the potential impact of climate change on the water sector. It is important to discuss the adaptation strategies while deliberating the key challenges and the risk associated. This event will serve as a platform to endow researchers with rational ideas and facilitate them with advanced methodologies related to water resources planning, design and management."

Speaking on the occasion, Prof Ajit K Chaturvedi, Director IIT Roorkee, said some of the key issues being faced by the country and the world at large would be identified at the conclave.

Hindustan Times (New Delhi)
The Statesman (New Delhi)
The Times of India (New Delhi)
The Indian Express (New Delhi)
The Hindu (Delhi)
Pioneer (Delhi)
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru)
☐ Deccan Chronicle
☐ The Economic Times (New Delhi)
☐ Business Standard (New Delhi)
☐ The Tribune (Gurugram)
☐ Financial Express
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)
☐ जनसत्ता (दिल्ली)
☒ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

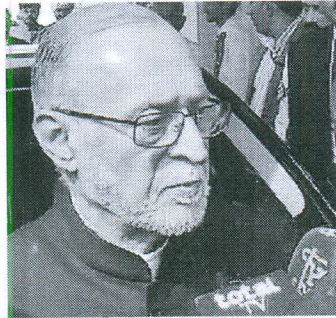
and documented at WSE Dte, CWC.

Dainik Bhaskar-2C

विस के विशेष सत्र के दूसरे दिन एलजी ने अभिभाषण में गिनाए सरकार के काम एलजी अनिल बैजल ने कहा-200 यूनिट बिजली और 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देती रहेगी आप सरकार

उपराज्यपाल बैजल का दो
बजे शुरू हुआ भाषण 11
मिनट तक चला

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली



सातवीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार के वादे दोहराए। बैजल ने 200 यूनिट बिजली, 20 हजार लीटर पानी फ्री देने के साथ ही भविष्य में 24 घंटे साफ पानी

लोगों को उपलब्ध कराने की बात कही। भाषण के बाद बैजल ने सभी विधायकों से शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए अपील की। उपराज्यपाल बैजल का भाषण

दोपहर ठीक 2 बजे शुरू हुआ और 11 मिनट तक चला। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में मेरी सरकार ने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महीने 20 किलो लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से लोगों के करीब ले जाना, दिल्ली के श्रमिकों को देश में सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी

देने जैसी जन-समर्थक योजनाएं शुरू कीं। इनके अलावा सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी एवं तीर्थ यात्रा योजना को व्यापक रूप से सराहा गया है। वर्तमान कार्यकाल में मेरी सरकार इन गतिविधियों को और आगे बढ़ाने और दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि जन-कल्याण के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता दस गारंटियों द्वारा सुनिश्चित की गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले जनता को दस गारंटियां दी थी।

सरकारों, नीतिकारों व वैज्ञानिकों को गंभीर होना होगा। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अगर नदियों को बचाना है, अगर तालाबों को जीवित रखना है तो ग्लेशियरों को मजबूत और समृद्ध रखना ही होगा।

ग्लेशियर बिना क्या जीवन बचा पाएंगे हम

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद



उत्तराखंड में सामाजिक कार्यों के लिए पद्मभूषण से सम्मानित। हिमालयन इनवायर्समेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक।

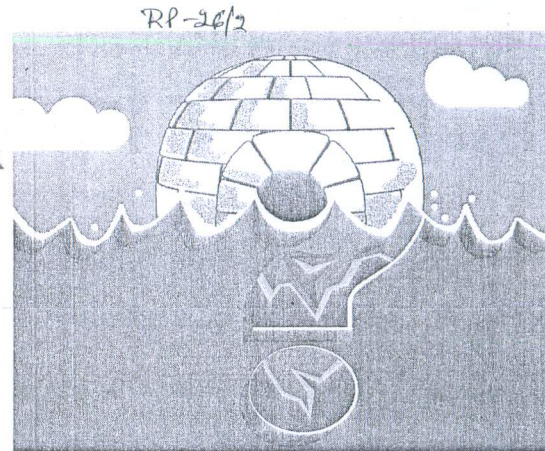
बढ़ते जलस्तर के खतरे की वास्तविकता को ऐसे समझें कि वर्ष 2100 तक हिंद महासागर में मौजूद मालदीव डूब जाएगा और इसी डर से आज वह भारत, श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया से जमीन खरीद अपने नागरिकों को जलवायु शरणार्थी बनने से बचाने में जुटा है।

ग्ले शियर दुनिया में एक तरह के पानी के बैंक हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट भी इन्हें माना जा सकता है। ये पृथ्वी का वही हिस्सा है जो दुनिया को एक बड़े रूप में पानी देते हैं। मतलब आप ये मानिए कि दुनिया के 75 फीसदी पीने के पानी के स्रोत ग्लेशियर ही हैं और लगभग 47 देशों में ये पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन से पहले ग्लेशियरों का अस्तित्व रहा है। अंटार्कटिका, अलास्का, ग्रीनलैण्ड व दुनिया भर के अन्य बड़े ग्लेशियर हैं और अपने देश में भी हिमालय एक बड़े ग्लेशियर की श्रेणी में आता है।

अकेले अंटार्कटिका के ग्लेशियर पूरी दुनिया के ग्लेशियर का 84 फीसदी भाग हैं। इसी से सभी महाद्वीपों में कहीं न कहीं पानी की व्यवस्था तय की जाती है। दुर्भाग्य यह है कि अब ग्लेशियरों के हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं, जिस पर बहस भी जारी है। ग्लेशियर के अध्ययन पर आधारित एक रपट यह दर्शाती है कि हर ग्लेशियर दुनिया में प्रति वर्ष 1-2 मीटर की गति से सिकुड़ता चला जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े जल संकट में ही नहीं अटकेगे, बल्कि समुद्र तल अप्रत्याशित रूप से इस हद तक पहुंच जाएगा कि दुनिया के कई प्रमुख देश व शहर डूब जाएंगे।

अभी हाल ही के मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा के एक ताजा अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के ही एक स्थान पर तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो दो साल पहले 2017 में करीब 17.5 डिग्री सेल्सियस था। लगातार अंटार्कटिका के बढ़ते हुए तापक्रम का सीधा और बड़ा मतलब यह है कि हम अपने ग्लेशियरों को तेजी से खो देंगे। ये भी सच है कि अंटार्कटिका जैसा स्थान जहां पर कभी भी 15 डि.से. तक तापक्रम नहीं देखा गया था, आज 50 वर्षों में इसका तापक्रम 5 डि.से. बढ़ा है। अध्ययन का एक हिस्सा यह भी था कि अगर गर्मी इसी अनुमान से बढ़ती रही तो करीब आने वाले 100 वर्षों में समुद्र तल 3 मीटर ऊपर चला जाएगा और ये दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही होगी। क्योंकि इन हालातों में अगर 1.42 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल गई तो ये समुद्र तल को 60 मीटर बढ़ा देगा और ये पृथ्वी पर प्रलय मचा देगा।

वैज्ञानिकों ने बार-बार यह चेतानी की कोशिश की है कि अंटार्कटिका पर औसतन



अंटार्कटिका में हाल ही तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो दो साल पहले 2017 में करीब 17.5 डिग्री सेल्सियस था। लगातार अंटार्कटिका के बढ़ते हुए तापक्रम का सीधा और बड़ा मतलब यह है कि हम अपने ग्लेशियरों को तेजी से खो देंगे।

1.9 किमी परत के रूप में मौजूद बर्फ अब बिखरने को है। इसके पिघलने की गति 1989 से 2017 तक 6 गुना बढ़ चुकी है और ये सिर्फ इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत तेजी से गर्मी अंटार्कटिका की सभी सीमाओं को तोड़ रही है। अब अगर आज के हालातों को देख लें तो वर्ष 2100 तक इतनी बर्फ पिघल जाएगी कि कई द्वीप, देश और 11 शहर इसमें डूब जाएंगे।

बढ़ते जलस्तर के खतरे की वास्तविकता को ऐसे समझें कि वर्ष 2100 तक हिंद महासागर में मौजूद मालदीव डूब जाएगा और इसी डर से आज वह भारत, श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया से जमीन खरीद अपने नागरिकों को जलवायु शरणार्थी बनने से बचाने में जुटा है। दूसरी तरफ ग्रीनलैण्ड के बारे में भी यही माना जा रहा है जो कि दुनिया में बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सदी के अंत तक यहां करीब 4.5 फीसदी बर्फ पिघल जाएगी और यह समुद्र के स्तर में 13 इंच की वृद्धि कर देगा।

'साइंस एडवांस' नामक पत्रिका में छपे एक अध्ययन के अनुसार ऐसा भी है कि करीब वर्ष 2030 तक अगर यही हालात रहे और इसी तरह गर्मी बढ़ती चली गई तो ग्रीनलैण्ड को पूरी

बर्फ पिघल जाएगी। अमरीका में अलास्का फेयरबैंक्स जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, आने वाले समय में ग्रीनलैण्ड कैसा दिखेगा, इसे लेकर उन्होंने एक तस्वीर पेश की है जो दर्शाती है कि आज पूरी तरह बर्फ से ढके ग्रीनलैण्ड में आपको हरियाली दिखाई देगी और ग्रीनलैण्ड की बर्फ को पिघलने से रोकना मनुष्य के लिये सबसे बड़ी चुनौती होगी।

करीब 6 लाख 60 हजार वर्ग किमी. में फैली हुई बर्फ 81 फीसदी ग्रीनलैण्ड को घेरे हुए है, जिसमें धरती के शुद्ध जल की बड़ी उपलब्धता मानी जाती है। यहां दुनिया के वो आठ मुख्य जल निकाय हैं जिनसे दुनिया को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। नासा के ऑपरेशन आइस ब्रिज के तहत वैज्ञानिक लगातार इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ग्रीनलैण्ड में बर्फ के स्तर में क्या परिवर्तन आएंगे। उनके अनुसार वर्ष 1991 और वर्ष 2015 के बीच ग्रीनलैण्ड की बर्फ की चादरों ने समुद्र स्तर में 0.02 इंच की वृद्धि की है और अगर ये वृद्धि इसी तरह होती रही तो ये तय मान लीजिए कि हालात और भी गंभीर हो जाएंगे।

ये इसलिए भी समझना जरूरी है कि दुनिया में जो तापक्रम वृद्धि तेजी से हो रही है उसका सीधा असर अगर कहीं पड़ता है तो ग्लेशियर पर। ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन के साथ ही जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें हिमालय भी है, जिसमें वर्ष 1982 से 2000 के बीच में करीब 1.5 डिग्री तापक्रम बढ़ा और प्रति वर्ष 0.6 डिग्री सेल्सियस की यहाँ बढ़ोतरी पाई गई है। यहां के बड़े ग्लेशियर चेनाब, पार्वती, वासप, गंगोत्री आदि हैं जिनमें वर्ष 1962 से वर्ष 2001 के बीच औसतन 400 मीटर की कमी आई है।

वैसे तो ग्लेशियरों को एक ऐसी संरचना के रूप में भी देखा जाता है जो गतिशील रहती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी वर्ष में वर्षा के योगदान से कितने ग्लेशियर बन पाए। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि शीतकालीन वर्षा के समय को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इस कारण ग्लेशियर की संरचना पर लगातार संकट बढ़ा है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ग्लेशियरों के बिगड़ते हालात की वजह ब्लैक कार्बन है जिसने अपनी बड़ी जगह बना ली है। साथ में घटते वन, वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं, मनुष्य जनित कचरा व ग्रीनहाउस गैस आदि जैसे तमाम कारक हैं जिन्होंने धीरे-धीरे दुनिया भर में ग्लेशियरों के हालात गंभीर कर दिए हैं।

सवाल ये पैदा होता है कि बात सिर्फ अंटार्कटिका, ग्रीनलैण्ड व हिमालय की नहीं है बल्कि आने वाले समय में इनके खत्म होने से बढ़ने वाले समुद्री जलस्तर और पीने के पानी की उपलब्धता की है। ये ये सवाल होंगे, जिनका शायद हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। अब नए सिरे से ग्लेशियर को लेकर सरकारों, नीतिकारों व वैज्ञानिकों को एक साथ मिल-बैठ कर गंभीर होना होगा और ये मानकर चलना होगा कि अगर नदियों को बचाना है, अगर तालाबों में लगातार पानी को सिंचित करना है और उन्हें जीवित रखना है तो ग्लेशियरों का महत्व समझना होगा। अंततः किसी भी संकट के समय हमें यदि कोई पानी उपलब्ध करा सकता है तो वे हैं हमारे ग्लेशियर। आने वाला समय इन्हीं के अस्तित्व पर निर्भर है। इसे गंभीरता से समझने की आज आवश्यकता है और आने वाला कल इसी पर निर्भर करेगा कि हम अपने ग्लेशियरों को कितना मजबूत और समृद्ध रखते हैं। ये बात तो साफ है कि जल है तो कल है और तब ही पानी का हर पल है।

बुलढाना के लिए मिट्टी बनी सोना

■ विनोद श्रीवास्तव

बुलढाना (महाराष्ट्र)। एसएनबी

अभी तक सिर्फ कहावत में सुना है कि कड़ी मेहनत से मिट्टी भी सोना बनती है, लेकिन महाराष्ट्र में यह हकीकत में चरितार्थ हो गया है। एक सुंदरसी सोच से सूखाग्रस्त विदर्भ के लोगों की तकदीर ही बदल गई है। यहां सूखे और वीरान पड़े तालाब (जलाशय) पानी से लबालब भर गए हैं। सिंचाई हो रही है, पशुओं को पानी मिल रहा है और लोगों को खेती व पीने के पानी के लिए सुविधा मिल गई है। यहां के 152 गांव में जैसे जिंदगी लौट आई हो।

दरअसल, सूखाग्रस्त विदर्भ में जल संकट किसी से छुपा नहीं है। यहां वर्ष के कुछ महीने इस कदर सूखा पड़ता है कि जमीनें सूखी हो जाती हैं और पानी के अभाव में लोग तथा मवेशी दूर चले जाते हैं, लेकिन केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सोच और प्रयास से विदर्भ का बुलढाना जिला जल संकट की समस्या से दूर होता जा रहा है। बुलढाना जिले में सड़क निर्माण



महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त विदर्भ में सूखे पड़े तालाब हुए पानी से लबालब

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी की सोच से बदली पश्चिमी विदर्भ की तस्वीर

गडकरी की राह पकड़ी महाराष्ट्र सरकार ने, एनएचआई के बाद लोक निर्माण विभाग ने अपनाया बुलढाना पैटर्न

की जिम्मेदारी के बीच मिट्टी की जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार से मिट्टी खरीदने के बजाय क्षेत्र में सूखे और वीरान होते तालाबों की खोज, फिर उनकी मिट्टी को निकालना और उनकी गहराई को बढ़ाना, जिससे तालाब में पानी का स्रोत व भंडारण बढ़ा और उसकी निकाली गई मिट्टी से सड़क बन गई।

मिट्टी सड़क बनाने के काम आई ही और तालाब से मिट्टी निकालने से जल संचयन बढ़ा और वाटर रिचार्ज की क्षमता बढ़ी। आसपास के कुओं में जल का स्तर

बढ़ा। इसका फायदा यह हुआ है कि अकेले बुलढाना जिले में 491 किलोमीटर (औरंगाबाद से नागपुर के बीच) सड़क निर्माण के लिए मिट्टी की जरूरत इन तालाबों से पूरी हुई और तालाब गहरे होने से यहां जल संचयन और वाटर रिचार्जिंग की क्षमता बढ़ गई। इससे यहां खेती की तीन फसलें होने की स्थिति पैदा हो गई। 152 गांव लाभान्वित हुए। पांच लाख आबादी को फायदा हुआ। 81 जल आपूर्ति के साधन सुलभ हुए, 2300 कुओं में पानी का स्तर 500 फीट से चढ़कर 40 फीट पर

आ पहुंचा और पूरे इलाके में 1525 हेक्टेयर भूमि खेती से लहरा उठी।

बुलढाना जिले में जल संग्रहण और भूमिगत जल स्तर बढ़ाने की एक सफल कहानी बन चुकी है। केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से एनएचआई ने 12 परियोजनाओं पर यह कार्य 2017 में शुरू किया था और अब तक 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। दिसम्बर 2020 तक शेष 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जल संचयन और रिचार्ज का बुलढाना पैटर्न बन गया है।

इस पैटर्न को एनएचआई के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग ने अपना लिया है। उसके तहत बनने वाले दो हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में बुलढाना पैटर्न को अपनाया जा रहा है कि जल संचयन के तालाब से मिट्टी निकालकर सड़क निर्माण में लगाया जा रहा है और तालाब गहरे हो रहे हैं, वे जल संचयन के काम आ रहे हैं। इस प्रयास से विदर्भ के लोगों में खुशी की लहर है।

लापरवाही : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी RP-26/2

यमुना में प्रदूषण का स्तर हुआ खतरनाक, सीपीसीबी ने नोएडा प्राधिकरण को बताया जिम्मेदार

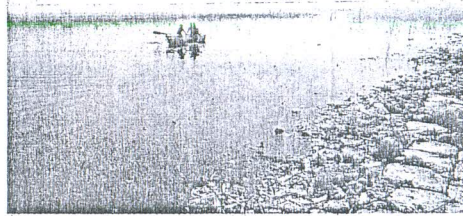
छोटे नालों का अशोधित पानी कोइली-शाहदरा के बड़े नाले में मिल रहा

आशुतोष पाठक
patrika.com

नोएडा. यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोएडा प्राधिकरण को बड़ा जिम्मेदार माना है। बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी अपनी फाइनल रिपोर्ट में दावा किया है कि नोएडा की ओर से छोड़ा

जा रहा अशोधित पानी सीधे कोइली और शाहदरा के बड़े नाले में मिल रहा है। इन दोनों ही नालों से गंदा पानी सीधे यमुना नदी में मिल रहा है, जिससे उसका प्रदूषण स्तर खतरनाक होता जा रहा है। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बड़े नालों में मिलने वाले शोधित पानी में बीओडी का स्तर करीब तीन गुना और सीओडी का स्तर करीब डेढ़ गुना अधिक मिला है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कोइली और शाहदरा नाले में प्रदूषण को लेकर अपनी



फाइनल जांच रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को सौंप दी है। रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण को उल्लेखित करते हुए कहा गया है कि इन दोनों नालों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत है। इसके तहत इन दोनों नालों में सीधे मिल रहे 30 छोटे नालों के अशोधित पानी को तुरंत रोकने की जरूरत है।

प्राधिकरण ने दिल्ली को ठहराया था जिम्मेदार

इससे पहले, प्राधिकरण के अफसरों ने सीपीसीबी को पत्र लिखकर यह दावा किया था कि 30 छोटे नालों के जरिये जो पानी छोड़ा गया, वह बाढ़ का पानी था। इसमें यह भी बताया गया कि इन दोनों ही नालों में प्राधिकरण की ओर से अशोधित पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इन दोनों ही नालों में प्रदूषण की बड़ी वजह दिल्ली की ओर से आ रहा अशोधित पानी है। हालांकि, अपनी जांच के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड के अफसरों ने बताया कि इन दोनों ही नालों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। यह यमुना नदी में प्रदूषण को बढ़ाने में बड़ा कारक साबित हो रहा है। बोर्ड के फसरों ने यह भी कहा कि नोएडा प्राधिकरण और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों के साथ मिलकर एक जांच टीम ने इन दोनों नालों का दौरा किया, जिसमें सेक्टर 24 और 23 में यह अशोधित पानी छोड़े जाने का नजारा दिखा।

खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण

जांच रिपोर्ट में यह संकेत मिले कि बायोकेमिकल ऑक्सीडाइज डिमांड (बीओडी) 94 मिलीग्राम प्रति लीटर और केमिकल ऑक्सीडाइज डिमांड (सीओडी) की मात्रा 364 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि सेक्टर 23 और 24 के छोटे नाले का अशोधित पानी सीधे बड़े नाले में मिल रहा है। बता दें कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड

और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी जल प्रदूषण को इंगित करते हैं। छोड़े गए पानी में बीओडी का स्तर 30 मिलीग्राम प्रति लीटर और सीओडी का स्तर 250 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में नोएडा की तरफ से नालों के जरिये छोड़े जा रहे पानी को तत्काल शोधित प्रक्रिया अपनाने की जरूरत बताई है।

पलामू जिले में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बदले मौसम से परेशानी

झारखंड में नदी की रेत पर बर्फ की चादर

14-26/2.

यह कश्मीर की वादी नहीं झारखंड का मेदिनी नगर है



मेदिनीनगर (पलामू) | संवाददाता

झारखंड के पलामू जिले में प्रकृति ने मंगलवार सुबह रौद्र रूप दिखाया। सुबह करीब 7:55 बजे तेज गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। इससे मेदिनी नगर से होकर बहने वाली उत्तर कोयल नदी की रेत पर बर्फ की चादर बिछ गई।

शाहपुर से शिवघाट तक रेत पर सफेदी ही सफेदी नजर आने लगी। बारिश रुकने के बाद बर्फ से पटी उत्तर कोयल नदी की रेत कश्मीर-मनाली में बर्फबारी का आभास करा रही थी। ओलावृष्टि चैनपुर प्रखंड के गरदा, बंदुआ, नेउरा आदि गांवों में भी काफी अधिक हुई है। इससे फसलों की भारी क्षति हुई है। पलामू के अन्य प्रखंडों में भी ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है।



पलामू जिले में हुई ओलावृष्टि के बाद मेदिनी नगर का दृश्य। लोगों के मुताबिक, क्षेत्र में ऐसी ओलावृष्टि कभी नहीं हुई। • हिन्दुस्तान

उत्तर प्रदेश



वाराणसी/गोरखपुर। वाराणसी समेत पूर्वांचल के सभी जिलों में मंगलवार को झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई।

झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि

बलिया के चंवरी गांव निवासी प्रभावती देवी पर मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। उधर, चंदौली के सदान गांव में छत पर उपले ढक रही राबिया बेगम की

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई तो देवरिया के रामपुर कारखाना में परीक्षा देने जा रहे अभिषेक यादव और भटनी में एक महिला की आकाशीय बिजली से मौत हो गई।

बिहार



वज्रपात से 11 लोगों की मौत

पटना। बिहार के कई जिलों में मंगलवार सुबह मौसम एकाएक बदला। पटना सहित लगभग सभी इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। कई जगह ओले भी पड़े। बेगूसराय, वैशाली, बांका, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं, राज्य के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात से 11 लोगों की जान चली गई।

पटना में सुबह 11.30 बजे से लगातार एक घंटे झमाझम पानी बरसा। इसके बाद दोपहर तीन बजे तक रुक-रुककर बारिश होती रही। क्षेत्र में 13.5 मिलीमीटर पानी बरसा। सबसे अधिक बारिश पूर्वी चंपारण जिले में हुई। यहां के चकिया में 64.2, पताही में 11.4, मेहसी में 9.6 और डेहरी व केसरिया में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण अधिकतम तापमान साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।

जलवायु संकट का संदेश दे रहा मौसम का बदलाव

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

दुनिया भर में बिगड़ रहा मौसम का चक्र

दुनिया के अलग-अलग देशों में भी मौसम चक्र बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। यूरोप में इस बार का जनवरी पहले की तुलना में काफी गर्म रहा। दूसरी ओर, दक्षिणी ध्रुव में पहली बार तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, 30 जनवरी को बंगलुरु में 33.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसे भी ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा गर्म दिन माना जा रहा है।

कुछ कहा जा सकेगा।

बीते साल भीषण ठंड और गर्मी बढ़ी: वर्ष 2019 में दिल्ली के लोगों ने भीषण ठंड के साथ ही काफी गर्मी भी झेली। यह लोगों के जेहन में अब भी ताजा है। दिल्ली के लोगों ने दिसंबर में ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा सर्दियां झेलीं। खासतौर पर 30 दिसंबर को अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस अवधि में अभी तक का सबसे कम अधिक तापमान था। 2019 में ही 11 जून को अधिकतम तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सबसे ज्यादा था।

जेडीए करवा रहा कायलाना के चारों ओर सड़क बनाने के लिए सर्वे

प्रकृति पर्यटन के लिए तीन चरण में होगा कायलाना विकास

RP-26/2

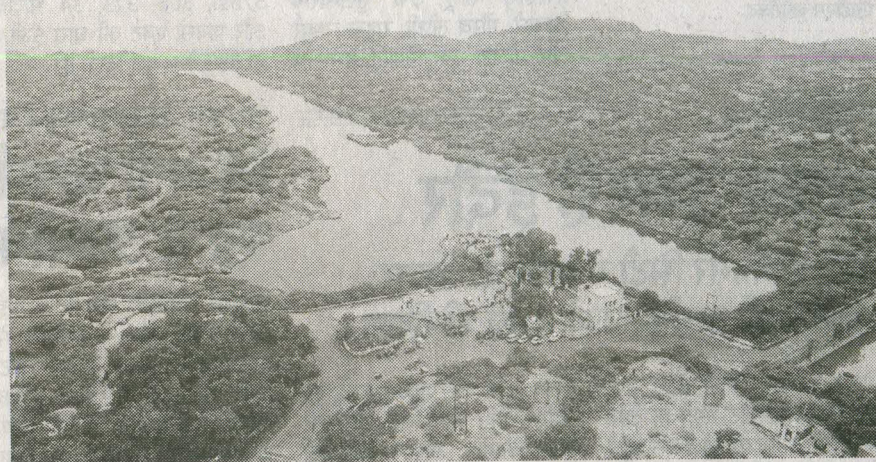


पत्रिका
ग्राउंड
रिपोर्ट

बायो डायवर्सिटी पार्क
व वाटर स्पोर्ट्स
एक्टिविटी पहले से ही
प्रस्तावित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जोधपुर. नेचर ट्यूरिज्म को विकसित करने के लिए शहर के सबसे बड़े वाटर पॉइंट में से एक कायलाना-तख्तसागर का चयन किया गया है। चार अलग-अलग विभाग इसके लिए काम करेंगे। जिला प्रशासन के निर्देशन में जेडीए, वन विभाग, आरटीडीसी व पीएचडी को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब कुछ ही दिनों में जेडीए इन जलाशयों के चारों ओर सड़क विकास का काम शुरू कर सकता है।



यह है पूरा प्रोजेक्ट

कायलाना-तख्तसागर के चारों ओर सड़क निर्माण करना है। पहले चरण में यह सड़क सिर्फ साइकलिंग व वॉकिंग, ट्रेकिंग के लिए ही खुली रहेगी। लेकिन इसके बाद इस पर यातायात संचालन भी हो सकता है। 5 लाख रुपए की राशि से कंसल्टेंसी ली जा रही है। जिसमें चौपासनी सड़क की ओर से आने पर सिद्धनाथ फांटा से कायलाना के दूसरी ओर

बिजोलाई के समीप सड़क तक इसको पूरा करने का प्लान है।

वर्तमान स्थिति

कायलाना चौराहे से जब तख्तसागर-कायलाना के मुख्य भाग तक पहुंचते हैं तो वहां से दो भागों में सड़क बंट जाती है। दोनों ओर सिंगल लेन सड़क है। एक सड़क तो बिजोलाई पैलेस रास्ते से होते हुए जैसलमेर बाइपास तक मिलती है। दूसरी ओर सिद्धनाथ फांटे से होते हुए चौपासनी रोड तक।



दो प्रोजेक्ट पहले से ही

1. आरटीडीसी को कायलाना में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें बोटिंग के साथ कई एडवेंचर स्पोर्ट्स भी शामिल किए जाएंगे।
2. वन विभाग को कायलाना के आस-पास की पहाड़ियों व फोरेस्ट क्षेत्र में नया बायो डायवर्सिटी पार्क विकसित करने को कहा गया है। इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर सीसीएफ जयपुर के पास भेजा गया है। अभी कागजी स्वीकृतियां आना बाकी हैं।

इनका कहना है...

फिलहाल कायलाना के चारों ओर सड़क की कंसल्टेंसी करवा रहे हैं। अभी इसका उपयोग पूर्ण यातायात के लिए होता है या सिर्फ चुनिंदा वाहनों के लिए। यह अभी तय होना बाकी है।

सुबोध माथुर, अधिशासी अभियंता, जेडीए जोधपुर।